श्रमिक महिलाओं एवं मानवाधिकार' की समस्या का अध्ययन

डॉ0 जितेंद्र प्रकाश त्यागी

सहा0 प्रा0 राजनीतिक विज्ञान विभाग

पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर ।

अंकित कुमार

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर ।

सार

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1998 की कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा ने वैश्विक श्रम मुद्दों के लिए एक दृष्टिकोण को औपचारिक रूप दिया, जिसे कोर लेबर स्टैंडर्ड्स (सीएलएस) के रूप में जाना जाता है। सीएलएस ने 'मानवाधिकारों' के विचारों से जुड़े सार्वभौमिक गुणों के प्रकार के रूप में श्रम मानकों के एक विशिष्ट सेट को विशेषाधिकार दिया है; जबरन और बाल श्रम का उन्मूलन, अवसर की समानता और ट्रेड यूनियन अधिकार। लेकिन इस 'मानवाधिकार' दृष्टिकोण का उन महिला श्रमिकों के दृष्टिकोण से क्या मतलब है जो दुनिया के कुछ सबसे वैश्वीकृत और असुरक्षित उद्योगों में रोजगार पर हावी हैं? इस लेख में, मैं सीएलएस में निर्धारित आर्थिक अधिकारों के लिए लिंग-अंध और नवउदारवादी-संगत दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण नारीवादी जुड़ाव का मामला बनाती हूं। कम से कम, यह लेख आर्थिक अधिकारों के दृष्टिकोण की अपर्याप्तता के बारे में व्यापक चिंताओं को उठाता है जो नवउदारवादी आर्थिक विकास प्रतिमान की (लिंग आधारित) संरचनाओं के भीतर काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सीएलएस ने श्रम मानकों के लिए एक स्वैच्छिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है जो वैश्विक निगमों द्वारा मानव अधिकारों के प्रचार और विनियमन को समस्या रहित मानता है। लेख इस परिप्रेक्ष्य को चुनौती देता है, महिलाओं के रोजगार और कॉर्पोरेट आचार संहिता के क्षेत्र में काम करने वाले कई नारीवादी विद्वानों के काम पर आधारित है। इन नारीवादी लेखों ने विशेष रूप से मानवाधिकारों की भाषा से परहेज किया है; इस प्रकार सीएलएस द्वारा महिलाओं की मानवाधिकार सक्रियता के लिए खोली गई संभावनाओं और सीमाओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है।

मुख्यशब्द: *श्रमिक महिला, मानवाधिकार'*

प्रस्तावना

नारीवादी विद्वानों ने लंबे समय से उस तरीके पर मुद्दा उठाया है जिसमें मानव अधिकारों की अवधारणाएं व्यापक पुरुष पूर्वाग्रह को दर्शाती हैं और महिलाओं की चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंडे में लाने की मांग की है। महिला मानवाधिकार प्रचारकों ने इस मानवाधिकार एजेंडे को पुनर्निर्देशित करने में कुछ सफलता का अनुभव किया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है, जो पहले मानवाधिकारों में नजरअंदाज किए गए निजी/घरेलू क्षेत्र के भीतर उल्लंघनों का पता लगाकर मानवाधिकारों की पुरुष-पक्षपाती सत्ता को चुनौती देते हैं। प्रवचन. इन नारीवादी बहसों पर प्रकाश डालते हुए और उन पर विचार करते हुए, यह लेख उस तरीके की जांच करता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिकवादी प्रवचनों को तेजी से आकर्षित किया है और इस मुद्दे के साथ महत्वपूर्ण नारीवादी जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस लेख का विशेष ध्यान 1998 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कोर श्रम मानकों (CLS) के लॉन्च पर है, जिसने श्रम मानकों के एक विशिष्ट सेट को विशेषाधिकार दिया - यह दर्शाता है कि इन मानकों में सार्वभौमिक नैतिक मानकों के गुण मौजूद हैं। 'मानवाधिकार' के विचार के साथ. सीएलएस में संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता, सभी प्रकार के जबरन और अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन और रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन शामिल है। और फिर भी, सीएलएस के भीतर गैर-भेदभाव की इस प्रतिबद्धता के बावजूद, उत्पादन की बहुराष्ट्रीय प्रणालियों के अंदर और बाहर महिला श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की महत्वपूर्ण पहचान के बिना मानक सामने आए हैं।

इस लेख में तर्क की दो मुख्य पंक्तियों को एक साथ लाया गया है। पहली चिंता श्रम मानकों की समकालीन चर्चाओं में निहित लैंगिक धारणाओं और शक्ति संबंधों को चुनौती देने की आवश्यकता से है, जो उन समस्याओं को उजागर करती है जो मानव अधिकारों (जैसे श्रम अधिकार) के रूप में आर्थिक अधिकारों की अवधारणाएं नारीवादी अनुसंधान और सक्रियता के लिए खड़ी करती हैं। दूसरा प्रश्न पूछता है कि श्रम मानकों पर नया 'मानवाधिकार' परिप्रेक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों के सामने आने वाले मुद्दों से किस हद तक निपट सकता है? इन मुद्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक नारीवादी क्षेत्रों में पाए जाने

वाले व्यापक कम वेतन और खराब कामकाजी स्थितियां शामिल हैं। इस प्रकार लेख की एक विशिष्ट चिंता यह पूछना है - क्या सीएलएस, जो कि बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक, नवउदारवादी-संगत, श्रम मानकों का एक सेट है, को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की सुरक्षा के साथ असंगत के रूप में देखा जा सकता है?

इस लेख के मूल में सैद्धांतिक धारणा है कि लैंगिक असमानता बाजार अर्थव्यवस्था की एक अभिन्न विशेषता है - इस प्रकार उदार आर्थिक प्रवचन में इस धारणा को चुनौती दी जाती है कि बाजार एक लिंग-तटस्थ स्थान है। यह तर्क दिया गया है कि महिलाओं के आर्थिक 'अधिकारों' की कोई भी समझ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वैश्विक लिंग संबंधों की वर्तमान असमान संरचनाओं के भीतर पर्याप्त रूप से महसूस किया जा सके। इन तर्कों को विकसित करने में, मैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उन लिंग आधारित दृष्टिकोणों का सहारा लेता हूं जो हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसके विश्लेषण के केंद्र में लिंग को स्थापित करने की चुनौती देते हैं। एक लिंग आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य, संक्षेप में, एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है - लिंग आधारित शक्ति संबंधों और धारणाओं को उजागर करना जो अर्थव्यवस्था की संकल्पना के स्पष्ट रूप से 'लिंग-तटस्थ' तरीकों को रेखांकित करते हैं। जिस तरह से लिंग-असमानता उत्पादन और रोजगार की वैश्विक प्रणालियों की एक मूलभूत विशेषता है, उस पर विचार करने में विफल रहने से, सीएलएस जैसे श्रम मानकों के दृष्टिकोण, जिसमें केवल गैर-भेदभाव और 'अवसर की समानता' के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है, आंशिक हैं और महिला श्रमिकों के कई समूहों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता अपर्याप्त है।

इस लेख के प्रारंभिक भाग में, मैं नारीवादी मानवाधिकार विद्वानों के काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो यह खोजते हैं कि नारीवादियों ने नारीवादी मानवाधिकार सक्रियता के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक अधिकारों की धारणाओं के साथ कैसे जुड़ाव किया है। उजागर की गई प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि हालांकि आर्थिक अधिकारों के विचार के इर्द-गिर्द कुछ नारीवादी सक्रियता रही है, इसने इस बात की आलोचना करने की कोशिश नहीं की है कि ILO (साथ ही विश्व बैंक) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्वयं आर्थिक अधिकारों की अवधारणाओं को कैसे नियोजित किया है। अधिकार। फिर लेख का ध्यान सीएलएस पर अधिक विशेष रूप से देखने की ओर जाता है; उनका निर्माण इस तरह से कैसे किया गया है जो मानव अधिकारों के प्रवचनों पर आधारित है, और इस 'मानवाधिकार' दृष्टिकोण की नारीवादी दृष्टिकोण से कैसे आलोचना की जा सकती है। विशेष रूप से सीएलएस के साथ

एक समस्या यह है कि वे श्रम विनियमन के लिए मूल रूप से स्वैच्छिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं, कार्यान्वयन के अपने सिद्धांत तंत्र (घरेलू कानून में अनुसमर्थन) से आईएलओ सम्मेलनों को अलग करते हैं, और स्वैच्छिक आचार संहिता जैसी चीजों के माध्यम से व्यापार 'स्व-नियमन' का समर्थन करते हैं। . लेख के अंतिम खंड में मेरा सुझाव है कि विनियमन के लिए ये 'नरम कानून' दृष्टिकोण एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें नारीवादी आवाज़ों ने सीएलएस की आलोचना की है। हालाँकि, हम पाते हैं कि श्रम मानकों के प्रति उभरते मानवाधिकार दृष्टिकोण का समर्थन करने के बजाय 'मानवाधिकार' परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है, इसके बजाय कार्यकर्ताओं और श्रमिकों को उनके सामने आने वाली समस्याओं के लिए व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं में संलग्न होने का तर्क दिया गया है।

मानवाधिकार, आर्थिक अधिकार और नारीवादी आलोचनाएँ

यहां मेरा इरादा महिला श्रमिकों और श्रम मानकों के मुद्दे को लिंग और मानवाधिकारों से संबंधित व्यापक नारीवादी बहस के संदर्भ में स्थापित करना है, इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है कि एक श्रेणी के रूप में आर्थिक अधिकार महिलाओं के मानवाधिकारों की समझ के लिए उत्पन्न होते हैं। महिलाओं की मानवाधिकार सक्रियता के उदय को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और इस फोरम में जिल स्टीन्स के लेख में इसे अधिक गहराई से कवर किया गया है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि युद्ध के बाद के युग में उभरे छोटे महिला मानवाधिकार आंदोलन का ध्यान दृढ़ता से आर्थिक अधिकारों पर केंद्रित था - यद्यपि संयुक्त राष्ट्र जैसी 'महिलाओं के मुद्दों' से निपटने वाली संधियों की सामग्री पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित था। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर राष्ट्र सम्मेलन (CEDAW)। हालाँकि, 1995 के बीजिंग सम्मेलन के समय तक, ध्यान स्थानांतरित हो गया था। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता VAW के मुद्दे को केंद्रीय बनाना था। वीएडब्ल्यू एजेंडा एक महत्वपूर्ण एजेंडा था क्योंकि इसने सीईडीएडब्ल्यू में सन्निहित 'अवसर की समानता' की चिंता को अधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकार नारीवाद के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। यह दृष्टिकोण मानव अधिकारों की मुख्यधारा की समझ के भीतर महिलाओं के अधिकारों की अनुपस्थिति की आलोचना में निहित था जो काम और नागरिक/राजनीतिक जीवन के सार्वजनिक दायरे में 'अधिकारों' को

स्थित करता था।

हालाँकि कई नारीवादी लेखकों ने सभी मानवाधिकारों (विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अविभाज्यता) की 'अविभाज्यता' के लिए तर्क दिया है, VAW के साथ चिंता से यह धारणा बन सकती है कि महिलाओं की मानवाधिकार सक्रियता इससे दूर चली गई है आर्थिक अधिकारों की चिंता. ग्रेवाल निश्चित रूप से यह विचार रखते हैं कि बीजिंग में VAW के इर्द-गिर्द एक अपेक्षाकृत आसान सहमति उभरी, जबकि यौन और प्रजनन अधिकार और आर्थिक अधिकार जैसे मुद्दे अत्यधिक विवादास्पद बने रहे।

आर्थिक अधिकारों के मुद्दे को कुछ नारीवादी लेखकों द्वारा संबोधित किया गया है। ये सभी लेख उन बाधाओं की ओर इशारा करते हैं जो नारीवादियों के लिए आर्थिक अधिकारों के साथ व्यवहारिक और वैचारिक रूप से समस्याग्रस्त हैं। सेफ़ के लिए, आर्थिक अधिकारों के साथ नारीवादी जुड़ाव की कमी सामाजिक-आर्थिक असमानता की जटिल प्रकृति के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण की व्यावहारिक सीमाओं को दर्शाती है; 'महिलाओं के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी दी गई संस्कृति की गहरी जड़ें जमा चुकी विशिष्टताओं, उसके वर्ग सीमांकन, और असमानता और पूर्वाग्रहों की उसकी परस्पर जुड़ी सामाजिक-आर्थिक जटिलताओं को ध्यान में रखने और उनका जवाब देने में असमर्थ है।'पीटरसन और पेरिसी सुझाव देते हैं कि आर्थिक अधिकारों की सीमाएं हैं इन व्यावहारिक बाधाओं से कम लेना-देना; अधिक महत्वपूर्ण वह तरीका है जिसमें मानवाधिकार विमर्श लैंगिक असमानता को प्रतिबिंबित करता है और उसका गठन करता है। इस प्रकार आर्थिक अधिकारों की सीमाएँ व्यापक 'विषमलैंगिकता' में पाई जाती हैं जो अधिकारों की प्रमुख समझ को रेखांकित करती है।

मानवाधिकारों को सार्वजनिक/निजी भेद पर आधारित माना जाता है जो मानवाधिकारों की प्रमुख समझ के भीतर पारंपरिक, पश्चिमी, विषमलैंगिक परिवार इकाई के विशेषाधिकार को दर्शाता है जो कई महिलाओं को अधिकारों तक पहुंच से वंचित करता है। उदाहरण के लिए, घर के भीतर श्रम का लिंग आधारित विभाजन और परिणामस्वरूप महिला कार्य का अवमूल्यन बाजार अर्थव्यवस्था के भीतर महिलाओं की 'माध्यमिक' स्थिति की धारणा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, जब महिलाएं औपचारिक रोजगार में प्रवेश करती हैं, तो वे ऐसा पुरुषों के साथ असमान शर्तों पर करती हैं। इसलिए, आर्थिक अधिकार, 'न केवल चुनौती देने

में विफल रहते हैं, बल्कि अक्सर संरचनात्मक अधीनता और महिलाओं के अधिकारों से इनकार को बढ़ा देते हैं।'

डायने एलसन आर्थिक अधिकारों के विचारों के साथ नारीवादी जुड़ाव पर संरचनात्मक सीमाओं को काफी अलग तरीके से देखते हैं। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की अभिव्यक्ति पर प्रमुख बाधा के रूप में अधिकारों के विमर्श की विषमलैंगिकता को देखने के बजाय, वह यह परिकल्पना प्रस्तुत करती है कि नवउदारवादी विकास प्रतिमान के भीतर महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की धारणाएँ असंगत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, नवउदारवादी मॉडल के भीतर संपत्ति रखने के अधिकार का केंद्रीय महत्व उन आर्थिक अधिकारों के विपरीत होने की संभावना है जिनमें पुनर्वितरण आयाम शामिल है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि (नवउदारवादी) विकास के भीतर मुख्यधारा के मानवाधिकारों को बाजारों के संचालन के पूरक के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, त्सिकाता ने 'विकास उद्योग' के भीतर - विशेष रूप से विश्व बैंक के विकास के लिए 'अधिकार आधारित दृष्टिकोण' (आरबीए) के भीतर लैंगिक मानवाधिकार प्रवचन के उपयोग पर प्रकाश डाला है। इन आरबीए ने अधिकारों के साथ नागरिकों के रूप में महिलाओं की स्थिति के आधार पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया है। यह एक नीतिगत बदलाव है जिसका कई महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक रूप से स्वागत किया है - यह दर्शाता है कि मानवाधिकार नारीवादी सक्रियता किस हद तक उस परिप्रेक्ष्य पर हावी है जो विशेष रूप से नवउदारवादी विकास प्रतिमान और महिलाओं पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित नहीं है।

(महिला) मानवाधिकार और मुख्य श्रम मानक

महिला श्रमिकों और श्रम मानकों पर अपने काम में, शॉ और हेल ने श्रम मानकों पर 'मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य' के रूप में समझे जाने वाले बदलाव पर ध्यान दिया - जिसे सीएलएस के उद्भव से उत्पन्न माना जाता है। मैं सीएलएस की लैंगिक आलोचना विकसित करने से पहले उनकी उत्पत्ति का संक्षेप में अवलोकन करूंगा। 1997 में, ILO के एक अधिकारी ने ILO के इन-हाउस जर्नल इंटरनेशनल लेबर रिव्यू में लिखा था कि मुख्य ILO मानकों में 'मानवाधिकार आयाम होने के साथ-साथ श्रम अधिकारों के प्रयोग के लिए मौलिक रूपरेखा की स्थिति भी है।' निकोलस वाल्टिकोस (यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आईएलओ के पूर्व सहायक महानिदेशक) ने भी नए सीएलएस दृष्टिकोण को सार्वभौमिक मानव अधिकारों की धारणाओं को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा, जो सुझाव देता है कि

'[i] इसे गलत नहीं माना जाएगा। घोषणा ऐतिहासिक है, क्योंकि यह मानवाधिकारों से सीधे संबंधित सभी क्षेत्रों में मुख्य आईएलओ मानकों को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा उपकरणों में एक नया आयाम जोड़ती है।' यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि आईएलओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है - विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में निर्धारित आर्थिक अधिकारों के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR)। हालाँकि, वाल्टिकोस और अन्य ने सीएलएस को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को प्रतिबिंबित करने वाले के रूप में देखा, जिनकी 'मौलिक' मानवीय मूल्यों के रूप में एक विशेष नैतिक स्थिति है। तो फिर, यह मानवाधिकारों से संबंधित एक स्पष्ट सार्वभौमिकतावादी स्थिति है। यह सीएलएस की मौलिक रूप से गलत समझ भी है। जैसा कि एल्टन ने तर्क दिया है, सीएलएस सार्वभौमिक मानव मानकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है:

[आधार - रेखा है की । . . सीएलएस में शामिल किए जाने वाले मानकों का चुनाव किसी सुसंगत सम्मोहक आर्थिक, दार्शनिक या कानूनी मानदंडों के लगातार आवेदन पर आधारित नहीं था, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उस समय क्या स्वीकार्य होगा, इसके व्यावहारिक राजनीतिक चयन को दर्शाता है।

सीएलएस शीत युद्ध की समाप्ति और डब्ल्यूटीओ के व्यापार विवाद तंत्र के भीतर 'सामाजिक खंड' के लिए कॉल की विफलता के बाद आईएलओ के भीतर संकट की अवधि से उभरा। एल्स्टन ने आईएलओ के प्रति अमेरिका की घटती प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया, जिससे पता चलता है कि अमेरिका एक श्रम मानक शासन स्थापित करने का इच्छुक था जो अनुसमर्थन मॉडल से दूर चला गया। परंपरागत रूप से ILO इस सिद्धांत पर काम करता है कि जिन राज्यों ने इसके विभिन्न सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं, वे उन्हें घरेलू कानून में अनुमोदित करेंगे। अनुसमर्थन पर अमेरिका के खराब रिकॉर्ड के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा। इस अर्थ में 'मानवाधिकारों' के संदर्भ में सीएलएस की बात, श्रम मानकों पर बहस के पतन के बाद श्रम मानकों पर 'नैतिक उच्च आधार' को फिर से हासिल करने के लिए आईएलओ (और वास्तव में अमेरिकी प्रशासन) के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व व्यापार संगठन.

उद्देश्य

1. श्रमिक महिलाओं एवं मानवाधिकारों का अध्ययन

2. श्रमिक महिलाओं और मानवाधिकारों के मुद्दे की जांच का अध्ययन

नारीवादी दृष्टिकोण से मुख्य श्रम मानक

नारीवादी लेखकों ने सुझाव दिया है कि सीएलएस का प्रचार श्रमिक अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में देखने को आगे बढ़ाता है जो अक्सर महिला श्रमिकों की विशिष्ट समस्याओं और चिंताओं को श्रम मानकों की बहस के किनारे छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, यह तर्क दिया गया है कि उभरते मानवाधिकार दृष्टिकोण से महिला श्रमिकों को उतना लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि कम वेतन और कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आम तौर पर 'मानवाधिकार' मुद्दे नहीं माना जाता है।

हालाँकि, हम सीएलएस की आलोचना को और आगे ले जा सकते हैं, यह सुझाव देते हुए कि ये मानक मूल रूप से असमान लिंग व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सीएलएस दृष्टिकोण वह है जिसे नवउदारवादी विकास प्रतिमान के भीतर (और यहां तक कि लाभ के लिए) काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भेदभाव न करने की प्रतिबद्धता महिलाओं के प्रजनन, घरेलू और गृहकार्य के निजी क्षेत्र को अदृश्य बना देती है। यह देखते हुए कि महिला श्रमिक सबसे कम भुगतान वाले क्षेत्रों और उद्योगों पर हावी हैं, सीएलएस की एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति जीवित मजदूरी अर्जित करने के अधिकार का मुद्दा है - कुछ ऐसा जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 में शामिल किया गया था। एफडीआई (श्रम लागत के आधार पर) के आकर्षण पर आधारित आर्थिक विकास के मॉडल पर जोर देने के कारण उचित मजदूरी के मुद्दे का गायब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो मुख्यधारा की विकास सोच पर हावी हो गया है। इस 'अधिकार' को किसी तरह सार्वभौमिक मानवाधिकार एजेंडे के परिधीय के रूप में प्रस्तुत करना, इस तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि अधिकारों के प्रकार जो दुनिया के सबसे गरीबों के लिए सार्थक परिवर्तन लाएंगे, वे किसी भी तरह से आर्थिक विकास मॉडल के साथ असंगत हैं जो कि वृद्धि की विशेषता है। रोजगार की असुरक्षा, क्योंकि श्रम बाज़ारों को और अधिक विनियमित और 'लचीला' कर दिया गया है।

आचार संहिता, स्वैच्छिक विनियमन और मानवाधिकार

सीएलएस के लिंग आधारित परिणामों से संबंधित एक और चिंता तब उठाई जा सकती है जब यह देखा जाए कि सीएलएस दृष्टिकोण ने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम मानकों को

लागू करने में सिद्धांत नियामक एजेंट के रूप में निगम की भूमिका को कैसे वैध बनाया है। एल्स्टन ने यह मुद्दा उठाया है कि सीएलएस दृष्टिकोण ने श्रम मानकों के प्रवर्तन और निगरानी में आईएलओ द्वारा विकसित कुछ ठोस नींवों को कमजोर करने का काम किया है। अप्रत्याशित रूप से, सीएलएस में मानवाधिकारों की भाषा की प्रधानता को देखते हुए, हम यह भी बता सकते हैं कि कैसे निगमों ने 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' और उनके कॉर्पोरेट आचार संहिता के बयानों में 'मानवाधिकारों' की भाषा को अपनाया है। स्वैच्छिकवाद पर यह बढ़ता जोर संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट में परिलक्षित होता है जिसने सीएलएस को निगमों के भीतर श्रम मानकों के प्रति प्रतिबद्धताओं के निर्माण के केंद्र में रखा है। 1999 में ग्लोबल कॉम्पैक्ट लॉन्च करते हुए, कोफी अन्नान ने तर्क दिया कि सीएलएस मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के साथ-साथ 'सार्वभौमिक मूल्यों' की एक प्रणाली का हिस्सा दर्शाता है और तर्क देता है कि 'ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें दुनिया भर के लोग अपने रूप में पहचानेंगे।

श्रम मानकों के प्रति इस स्वैच्छिक दृष्टिकोण को निर्देशित करने वाला मुख्य तंत्र कॉर्पोरेट आचार संहिता है। कोड में आम तौर पर काम के माहौल और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यूनतम श्रम शर्तों का विवरण शामिल होता है, यह आश्वासन दिया जाता है कि फर्म स्थानीय कानूनों का पालन करेगी और गारंटी देती है कि फर्म भेदभाव-विरोधी रोजगार प्रथाओं को बनाए रखेगी। आश्चर्य की बात नहीं है कि आचार संहिता के दृष्टिकोण की पूरी तरह से आलोचना की गई है। इस मुद्दे पर कंपनियों को अनिवार्य रूप से स्व-विनियमन करने की अनुमति देने की नैतिकता के बारे में चिंताएँ उठाई गई हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कोड को बाध्यकारी नियामक प्रतिक्रियाओं के विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए जबकि उन्हें वास्तव में उनके पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उविन की चिंता पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए कि 'अधिकारों' की बात अभिनेताओं को एक 'नैतिक उद्देश्य' प्रदान करती है जो उनकी गतिविधियों को वैध बनाती है।

लिंग निर्धारण आचार संहिता: नारीवादी सक्रियता और अनुसंधान

विभिन्न नारीवादी अध्ययनों में आचार संहिता से जुड़ी समस्याओं को चतुराई से उजागर किया गया है। यहां मैं इनमें से कुछ अध्ययनों का अवलोकन कर रहा हूं ताकि सबसे पहले यह प्रदर्शित किया जा सके कि कॉर्पोरेट आचार संहिता के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धताएं कैसे विफल हो जाती हैं

महिला श्रमिकों को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे, यह शोध महिलाओं के रोजगार की चर्चा में सीएलएस के 'मानवाधिकार दृष्टिकोण' की व्यवहार्यता से संबंधित और प्रश्न उठाता है। यह सुझाव दिया गया है कि सीएलएस में समर्थित मुद्दों के प्रकार और, परिणामस्वरूप, कोड में भी प्रतिबिंबित होने से अक्सर महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं होता है।

पियर्सन और सेफैंग के महिलाओं और आचार संहिता के अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो श्रम बाजार में उनकी कथित 'माध्यमिक' स्थिति से उत्पन्न होती हैं। इनमें शामिल हैं: कम वेतन और वेतन असमानता, गर्भवती श्रमिकों के लिए सुरक्षा और सम्मान की कमी, अपर्याप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा अधिकार (विशेषकर अंशकालिक श्रमिकों के लिए), संघ की स्वतंत्रता का अभाव, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार और मानवाधिकार, लागू ओवरटाइम और लंबे कार्य दिवस और काम की तीव्रता। इसके अलावा, वे महिला गृहकार्यकर्ताओं और बाल श्रम से संबंधित मुद्दे भी उठाते हैं जिनका महिला श्रमिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण के लिए, क्योंकि गृहकार्य करने वाले लोग कारखानों की तुलना में कहीं अधिक खराब परिस्थितियों में काम करते हैं, श्रमिकों पर न्यूनतम कामकाजी स्थितियां लागू करने वाले कोड लागू करने से दुनिया में महिलाओं के कुछ सबसे गरीब समूहों की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वेतनभोगी रोज़गार खोजने के लिए। महिलाओं और आचार संहिता के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों और अभ्यासकर्ताओं ने भी कई व्यावहारिक समस्याओं की ओर इशारा किया है - सबसे विशेष रूप से, महिलाओं को अक्सर पता नहीं होता है कि कोड मौजूद भी हैं। वे कोड की निगरानी और सत्यापन के लिए 'टिक-बॉक्स' दृष्टिकोण की ओर भी इशारा करते हैं, जिसके तहत स्वतंत्र निगरानी संगठन (जैसे अकाउंटेंसी और कंसल्टेंसी फर्म) आम तौर पर महिला श्रमिकों से बात करने में विफल रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी प्रबंधकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर रहते हैं। लागू किया जा रहा है. ऐसी स्थिति उन कोडों के कार्यान्वयन की ऊपर से नीचे की प्रकृति का संकेत है जो महिलाओं के रोजगार की वास्तविकता को ध्यान में रखने में विफल हैं, जिससे 'इस प्रक्रिया में महिला श्रमिकों या उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई जगह नहीं है'। शॉ और हेल के काम में प्रतिबिंबित एक खोज:

यह विशेष रूप से जमीनी स्तर के महिला कार्यकर्ता संगठनों के साथ हमारा जुड़ाव है जिसने

हमारे विचार को सूचित किया है कि जिस तरह से नैतिक व्यापार आंदोलन विकसित हुआ है उसमें प्रमुख समस्याओं में से एक शीर्ष से नीचे का तरीका है जिसमें कोड अपनाए गए हैं। आचार संहिता आम तौर पर श्रमिकों की जानकारी या सहमति के बिना उनकी ओर से पेश की जाती है। बस यह मान लिया गया है कि श्रमिक इन पहलों को अपने हित में देखेंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि कोड के एक उच्च अनुपात में भेदभाव-विरोधी प्रतिबद्धता शामिल है, यह कार्यबल में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को बढ़ाने में बहुत कम योगदान देता है। कुछ मामलों में यह आचार संहिता के साथ जुड़े कमजोर प्रवर्तन तंत्र को दर्शाता है। हालाँकि भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के प्रावधान कोड में लिखे गए हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किस तरह से वैश्विक श्रम बाजारों में लैंगिक असमानता की संरचनाएं मौजूद हैं और कंपनियों ने किस तरह से इसे कायम रखा है और इसे आगे बढ़ाया है।

कम लागत वाली महिला श्रम की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए ये लैंगिक असमानताएँ। उदाहरण के लिए, अधिकांश कोड से होमवर्क करने वालों का बहिष्कार इस बात का संकेत है कि किस तरह से कोड असमानता के अंतर्निहित लैंगिक रूपों से निपटने के लिए एक अपर्याप्त उपकरण हैं जो उत्पादन की बहुराष्ट्रीय प्रणालियों की विशेषता रखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी बागवानी में महिलाओं के रोजगार पर बैरिएंटोस, मैक्लेनाघन और ऑर्टन के काम में एक और समस्या उभर कर सामने आती है।

उन्होंने पाया कि कोड अक्सर महिला श्रमिकों के बड़े समूहों को कवर करने में विफल रहते हैं। उनके अध्ययन में, महिला श्रमिकों को आम तौर पर अस्थायी अनुबंध पर नियोजित किया गया था और इसलिए उन्हें संहिता के प्रावधानों में शामिल नहीं किया गया था। यह मुद्दा उठाया गया है कि आचार संहिता रोजगार से संबंधित मानदंडों के आसपास तैयार की गई है जो पूर्णकालिक, स्थायी रोजगार के पुरुष अनुभव के प्रति पक्षपाती हैं। इसलिए, 'खतरा यह है कि पुरुष स्थायी कार्यकर्ता के अनुभव को आदर्श माना जाता है और नव-पितृवादी संबंधों की अधिक सूक्ष्म जटिलताओं के कारण महिलाओं के रोजगार को ध्यान में नहीं रखा जाता है।' ये अध्ययन क्या सुझाव देते हैं कॉर्पोरेट आचार संहिता ने, सीएलएस की तरह, श्रमिक अधिकारों के संबंध में एक सार्वभौमिक स्थिति अपनाई है जो पुरुष कार्यकर्ता की भूमिका और स्थिति को दर्शाती है। ये ऐसे मानक हैं जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों

(उदाहरण के लिए, औपचारिक रोजगार) की धारणा से जुड़े हुए हैं और उन तरीकों को संबोधित करने में विफल हैं जिनमें घरेलू सेटिंग में महिलाओं का काम हो सकता है या घरेलू बोझ जो औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर भी पड़ता है। कंधा देने को मजबूर.

निष्कर्ष

सीएलएस और कॉर्पोरेट आचार संहिता दोनों में समस्याओं को उजागर करने का मतलब है कि कई विद्वान मानवाधिकार दृष्टिकोण को महिला श्रमिकों के बड़े समूहों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों को ध्यान में रखने में विफल मानते हैं। यह आशंका भी जताई गई है कि मानवाधिकार दृष्टिकोण का प्रभाव महिलाओं के लिए रोजगार ढूंढना अधिक कठिन बनाने का हो सकता है। पियर्सन और सेफैंग के अध्ययन में महिलाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थीं कि वे बेहतर स्थिति में भी निर्यात क्षेत्र के कारखानों में काम करना जारी रख सकेंगी। इसी तरह, ब्रिल ने पाया कि आचार संहिता के अस्तित्व से गृहकार्य करने वालों (जो मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं) को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है और श्रम विनियमन के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो श्रमिकों को जीविकोपार्जन जारी रखने में सक्षम बनाता है। हाल के एक लेख में, नैला कबीर विशेष रूप से श्रम मानकों की बहस (विशेष रूप से एक सामाजिक खंड के विचार) की आलोचना करती हैं। बांग्लादेशी महिला श्रमिकों के बीच अपने शोध के आधार पर, वह सुझाव देती हैं कि परिधान उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर सक्रिय अभियानों के फोकस ने उन कई लाभों पर विचार करने की उपेक्षा की है जो निर्यात क्षेत्र के उत्पादन में रोजगार महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार की तुलना में प्रदान करता है। और फिर भी, आचार संहिता को अक्सर महिलाओं की सक्रियता के लिए एक अवसर प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है - एक ऐसा स्थान जो महिलाओं को व्यावहारिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। साहित्य में एक सामान्य स्वीकृति है कि कोड अंततः श्रम मानकों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिससे महिला श्रमिकों को लाभ होगा। ये लेख स्वयं महिला श्रमिकों के सहयोग से कोड विकसित करने का आह्वान करते हैं। लेकिन जबकि श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले श्रम मानकों को तैयार करने में आचार संहिता की संभावित भूमिका की सामान्य स्वीकृति है, श्रम मानकों की बहस के भीतर 'मानवाधिकारों' की भाषा के साथ महत्वपूर्ण नारीवादी जुड़ाव के कम सबूत हैं। इस लेख में प्रस्तुत सीएलएस की आलोचना से आगे बढ़ते हुए, उन संभावनाओं और सीमाओं के बारे में सवाल उठाए जाने की जरूरत है जो सीएलएस एजेंडा महिलाओं की मानवाधिकार सक्रियता के लिए खोलता है।

संदर्भ

[1] एबर, एल. और एल. रॉलिंग्स। 2021. प्रोत्साहन-आधारित सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों पर उत्तर-दक्षिण ज्ञान साझा करना। एसपी चर्चा पत्र संख्या 1101. वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक।

[2] ब्रैडशॉ, एस. 2018. "संरचनात्मक समायोजन से सामाजिक समायोजन तक: मेक्सिको और निकारागुआ में सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का एक लिंग आधारित विश्लेषण।" वैश्विक सामाजिक नीति, 8, सं. 2: 188-207

[3] CEDAW समिति (महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति)। 1991a. "सामान्य अनुशंसा संख्या 16 (दसवां सत्र, 2021): ग्रामीण और शहरी पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक महिला श्रमिक।"

[4] सीईआरडी समिति। 2020. "सामान्य अनुशंसा संख्या 25: नस्लीय भेदभाव के लिंग संबंधी आयाम।"

[5] जप करें. एस. 2018. "'गरीबी का नारीकरण' और 'गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों का नारीकरण': संशोधन की गुंजाइश?" जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, 43: 165-197।

[6] एंगल, के. 2015. "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और नारीवाद: जब प्रवचन मिलते रहें।" अंतर्राष्ट्रीय कानून में: आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण। डी. बस और ए. मांजी (सं.)। पोर्टलैंड, OR: हार्ट पब्लिशिंग, पीपी. 47-66

[7] एंगल, के. 2015. "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और नारीवाद: जब प्रवचन मिलते रहें।" अंतर्राष्ट्रीय कानून में: आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण। डी. बस और ए. मांजी (सं.)। पोर्टलैंड, OR: हार्ट पब्लिशिंग, पीपी. 47-66

[8] होम्स, आर. और एन. जोन्स। 2023. विकासशील विश्व में लिंग और सामाजिक संरक्षण: माताओं और सुरक्षा जाल से परे। लंदन और न्यूयॉर्क: जेड बुक्स।

[9] सिपुलेवेडा, एम. और सी निस्ट। 2022. सामाजिक सुरक्षा के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण। हेलसिंकी: फिनलैंड के विदेश मंत्रालय।हिलेरी चार्ल्सवर्थ, 'द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन', इंटरनेशनल फेमिनिस्ट जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, 4 (2002), पी। 432

[10] सुज़ाना टी. फ्राइड, महिलाओं के मानवाधिकारों की अविभाज्यता: एक सतत संवाद (न्यू जर्सी: महिलाओं के वैश्विक नेतृत्व केंद्र, रटगर्स विश्वविद्यालय, 2014)।

[11] इंदरपाल ग्रेवाल, 'ऑन द न्यू ग्लोबल फेमिनिज्म एंड द फैमिली ऑफ नेशंस: डिलेमास ऑफ ट्रांसनेशनल फेमिनिस्ट प्रैक्टिस', एला शोहट (एड.) में, टॉकिंग विज़न: मल्टीकल्चरल फेमिनिज्म इन ए ट्रांसनेशनल एज (न्यूयॉर्क: एमआईटी प्रेस, 2018), पी . 519.

[12] हुडा ए. सेफ, 'संदर्भित लिंग और श्रम: येमिनी सामाजिक-अर्थव्यवस्था में वर्ग, जातीयता और वैश्विक राजनीति', जूली पीटर्स और एंड्रिया वोल्पर (संस्करण), महिला अधिकार, मानवाधिकार: अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी परिप्रेक्ष्य (लंदन: रूटलेज,) में 2015), पी. 229.

[13] डायने एलसन, 'जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड नियो-लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज', मैक्सिन मोलेनेयक्स और शारा रजावी (संस्करण), जेंडर जस्टिस, डेवलपमेंट एंड राइट्स (ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2022), पीपी. 78-114 में।

[14] द्ज़ोडज़ी त्सिकाता, 'विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: समान परिवर्तन या उससे अधिक की संभावना?', आईडीएस बुलेटिन, 35 (2014), पीपी 130-3।

[15] विश्व बैंक, एन्जेंडरिंग डेवलपमेंट: थ्रू जेंडर इक्विटी इन राइट्स, रिसोर्सेज एंड वॉइस (ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर द वर्ल्ड बैंक, 2021) भी देखें।

[16] मार्था नुसबौम, 'महिलाएं और समानता: क्षमताएं दृष्टिकोण', अंतर्राष्ट्रीय श्रम समीक्षा, 138 (2019), पीपी. 227-45।

[17] मार्था नुसबौम, 'महिला क्षमताएं और सामाजिक न्याय', मैक्सिन मोलेनेयक्स और शारा रज़ावी (संस्करण), लिंग न्याय, विकास और अधिकार (ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2022), पीपी। 45-77 में।